...(*Interruptions*)... I am sorry. I don't see why hon. Members who are fully familiar with the procedure of the Question Hour ...(*Interruptions*)... No, you cannot do it. ...(*Interruptions*)... One minute, please. Let us be very clear. Who ask the primary question? The right to ask supplementaries belongs to the person who asks the primary question. Other supplementaries are a matter of courtesy. ...(*Interruptions*)... The rule of this House, ...(*Interruptions*).. Just a minute, please. Let me put the record straight. The rule of this House -- and it was not made by me -- was two supplementaries. I have expanded it to three supplementaries. I have to be fair to others who ...(*Interruptions*)... No, you cannot do that. ...(*Interruptions*)... शरद जी, ऐसा है, देखिए, the question and two supplementaries is the established practice. Then, additional supplementaries have been allowed. My predecessor had restricted it to two additional supplementaries. I have expanded it to three. Now, if I expand this further, then somebody else's chance goes down, and I don't see why the next person should be deprived of his right. That's all. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... देखिए, it is not by subject. ...(*Interruptions*)... It is not by subject. It is a fair system. The Starred Questions are balloted, publicly balloted; hon. Members witness it. After that, if the chance does not come, what is the Chair to do? The Chair has nothing to do with the balloting. I have the list of questions given. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती मोहसिना किदवई : चेयरमैन सर, मेरी बात तो सुन लीजिए...**(व्यवधान)**...

†**محترمہ محسنہ قدوائی** : چیئرمین سر، میری بات تو سن لیجئے ---**(مداخلت)**---

श्री सभापति : देखिए, मेरी आपसे गुज़ारिश है कि ...**(व्यवधान)**... अगर 10 लोग यही बात कहेंगे तो ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती मोहसिना किदवई : शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मेरा नोटिस भी था, वह भी नहीं माना गया। ...**(व्यवधान)**...

†**محترمہ محسنہ قدوائی** : شارٹ ڈیوریشن کے لئے میرا نوٹس بھی تھا وہ بھی نہیں مانا گیا۔

श्री सभापति : देखिए, आप टाइम निकालिए, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ...**(व्यवधान)**... If the House is extended by the Government, I have no problem in listing all these things. Yes, Dr. Mitra.

Laying of gas pipeline from Bathinda to Srinagar

*182. DR. CHANDAN MITRA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government had decided to lay gas pipeline from Bathinda to Srinagar, *via* Jammu;

†Transliteration in Urdu Script.

(b) if so, the progress of work in this regard along with the target date for its completion; and

(c) fresh steps taken by Government to expedite the project and also its time-bound completion?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): (a) to (c) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) has authorized GSPL India Gasnet Limited (GIGL), a Special Purpose Vehicle of Gujarat State Petronet Ltd. (GSPL), Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL), Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL) and Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL), for laying of natural gas pipeline from Bathinda to Srinagar *via* Jammu.

(b) The original completion date for laying the pipeline project was 6.7.2014. However, the project got delayed due to absence of anchor load customers and non-availability of statutory/forest clearances from the State Governments. The completion date will depend on the receipt of clearances from the statutory authorities. The total length of the pipeline is 725 kms. As far as Right of Use (RoU) of land is concerned, Notifications under Sections 3(1) and 6(1) of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (P&MP Act) have been published for 452 km and 394 km respectively.

(c) Ministry is facilitating GIGL in acquisition of Right of Use of land in accordance with provisions of Petroleum and Minerals Pipelines Act, 1962.

DR. CHANDAN MITRA: Sir, while the Minister has given some details about the delay of the project and so on, I have one fundamental question. I find from the reply that there is no date at all set for completion of the project. It was originally supposed to be completed on 06.07.2014. Now, almost one year later, the project is not complete, and no target date has been set. I think, this is a serious lapse. So, I would like to know from the Minister, through you, Sir, whether the Government has decided on a fresh completion date.

श्री धर्मेंद्र प्रधान : चेयरमैन सर, मूल प्रश्न में एक डेट सही तरीके से माननीय सदस्य को बताई गई है कि 06.07.2014 तक यह परियोजना कम्प्लीट हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब इस पाइपलाइन की viability के लिए PNGRB ने Feasibility Report आने के बाद उसको बिड किया, तो इसके दो कारण सामने आए। एक तो उसके एंकर लोड ग्राहकों की अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है अथवा उसकी मार्केटिंग लाइन क्या होगी, इसकी व्यवस्था भी नहीं हो पाई है।

दूसरा, दो राज्यों के अन्दर Right of Utility (RoU) के लिए जो अधिकार चाहिए था, जम्मू-कश्मीर की सरकार ने वह अधिकार अभी-अभी दिया है। इतने बड़े infrastructure project में उसकी जो दो मूल शर्तें हैं, उसके बारे में हमने उत्तर में बताया भी है। जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से RoU की अनुमति अभी-अभी आई है। फिर जब तक एंकर लोड ग्राहकों की स्पष्टता नहीं होगी, तब तक यह सम्भव नहीं होगा। उसको बनाने वाला एक consortium है और PNGRB को यह दिया गया है। इन सब कारणों से इसको एक स्पेसिफिक डेट के साथ जोड़ना संभव नहीं होगा।

DR. CHANDAN MITRA: Sir, this is rather disappointing that we don't have any idea of the date of completion. But I would like to know from the Minister, through my second supplementary, what the problem is as of now. Is it only land acquisition and right of use, or, is there any other problem which has stalled the project? And, has any work happened on the ground in the project, or, are we still talking only of acquisition of land and other technical requirements? Has any progress happened? If so, how many kilometres of the pipeline have been completed?

श्री धर्मेंद्र प्रधान : चेयरमैन सर, पाइपलाइन तो अभी बनी ही नहीं है। प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने स्पष्टता के साथ यह बताया है कि जब तक PNGRB को इसके एंकर लोड ग्राहक नहीं मिलते हैं, तब तक यह सम्भव नहीं होगा। उन्होंने टेंडर भी किया है, लेकिन अभी टेंडर बिड खुला ही नहीं है। जब टेंडर बिड ही नहीं खुला है, तो उसको इम्प्लिमेंट करने का विषय ही कहां आता है?

यह एक टेक्नो-इकोनॉमिक इश्यू है। जिस समय, पिछले दिनों में PNGRB ने Feasibility Report दी थी, तो अनुभव में यह आ रहा है कि उसको उस इलाके में ग्राहक ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में दोनों राज्यों की राज्य सरकारों के साथ बैठकर इस बारे में उसको सोचना पड़ेगा। इसके साथ ही दो-चार अन्य सम्बन्धित मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी बैठकर बात करनी पड़ेगी कि इसके साथ क्या कोई Gas Based Power Plant, Fertilizer Plant या Food Processing Plant आ सकता है? जब तक उसका मार्केट नेटवर्क खड़ा नहीं हो पा रहा है, तब तक इसको करने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए टेंडर होने के बाद भी उसकी बिड को अभी तक खोला नहीं गया है।

SHRI RANJIB BISWAL: Sir, the hon. Minister hails from my State although he represents Bihar in the Rajya Sabha. So, Sir, I believe, he has a soft corner for Odisha, at least. My question to the hon. Minister is this. There is an Indian Oil Refinery in Paradip where a pipeline has to be laid from Paradip to Haldia. Sir, I would like to know ...

MR. CHAIRMAN: One minute. Please ask on the question.

SHRI RANJIB BISWAL: Sir, I am asking the question.

MR. CHAIRMAN: No, this is not the question.

SHRI RANJIB BISWAL: Sir, since he is from Odisha, I am asking the question. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: It doesn't matter where he is from. ...(*Interruptions*)...

SHRI RANJIB BISWAL: Sir, if he has the information,

MR. CHAIRMAN: I am sorry.

SHRI RANJIB BISWAL: Sir, if he has the information,

श्री सभापति : देखिए, यह मत कीजिए।

SHRI RANJIB BISWAL: It is important. It is regarding Odisha. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Why are you wasting time like this? You know what the question is. ...(*Interruptions*)... Shri Sanjay Raut. ...(*Interruptions*)...

SHRI RANJIB BISWAL: Sir, can I ask the question? Sir, I want the Minister to reply as to when the project will be completed.

MR. CHAIRMAN: You can take it up with him separately.

श्री संजय राउत : सर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जम्मू-कश्मीर हमारे देश का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण राज्य है और डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत जम्मू-कश्मीर में है, जो होनी चाहिए।

सर, भटिंडा से श्रीनगर वाया जम्मू जो गैस पाइपलाइन का निर्माण हो रहा है, वह 725 किलोमीटर लम्बी पाइपलाइन है। उस पाइपलाइन के लिए जो भूमि लगेगी, उसमें थोड़ी पंजाब की होगी और सबसे ज्यादा श्रीनगर और जम्मू की भूमि लगेगी। तो मेरा प्रश्न है कि इसके लिए जो भूमि सरकार लेने वाली है, तो क्या आप उस भूमि का अधिग्रहण, अब जो नया भूमि अधिग्रहण कानून आ रहा है, उस कानून से करेंगे? इसके लिए आपको कितनी भूमि चाहिए और कितनी भूमि का अधिग्रहण हो गया है? अगर यह नहीं हुआ है, तो हमारा जो नया Land Acquisition Act अब बन रहा है, आप उस कानून से उस भूमि का अधिग्रहण करेंगे या नहीं?

श्री धर्मेंद्र प्रधान : महोदय, कुल 725 किलोमीटर लम्बी इस पाइपलाइन में पंजाब का हिस्सा 410 किलोमीटर है और जम्मू-कश्मीर का 315 किलोमीटर है। सर, जब 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून को संशोधित किया गया, तो कुछ सेक्टर्स को उसमें से बाहर रखा गया, मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए बाहर रखा गया। ऐसे 13 segments हैं, 13 विषय हैं, जिनको इससे बाहर रखा गया। मैं माननीय सदस्य को बाद में अवगत कराऊँगा कि क्या हमारी पाइपलाइन भी उनके अन्दर आती है। अभी मेरे पास तथ्य नहीं हैं और मैं भी खुद स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन क्या उन 13 catagories के अन्दर पाइपलाइन भी आती है, अगर यह आती है, तो शायद उसका काम पुराने कानून के हिसाब से चलेगा। मैं वही तथ्य माननीय सदस्य को दे दूँगा।

डा. एम. एस. गिलः सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। यह पाइपलाइन लग रही है, लगनी चाहिए और वह जल्दी लगनी चाहिए, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। इससे बहुत फायदा होगा। यह भटिंडा से जायेगी, लेकिन यह सारे पंजाब में से काटकर जायेगी, आगे जम्मू वगैरह भी काटेगी। लेकिन, पंजाब में तो बहुत महँगी और बहुत कीमती जमीन है और तो कुछ हमारे पास है ही नहीं। तो यह जो Right to use आप इस्तेमाल कर रहे हैं,

इसका मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन उसमें आप किसानों के साथ धक्केबाजी तो नहीं कर रहे हैं, जो 60 सालों से हिन्दुस्तान में Land Acquisition और अन्य सारे rights में आदत रही है? मुझे आप यह assure कीजिए कि क्या आप उनको जो भी देना चाहिए, वह देंगे या आप कहेंगे कि हम तो जा रहे हैं, देश का काम हो रहा है?

श्री धर्मेंद्र प्रधानः चेयरमैन सर, ऐसा अनुभव मोटा-मोटा पाइपलाइन सेक्टर में नहीं है। गैस हो या क्रूड ऑयल हो, देश में 15 हजार किलोमीटर लम्बी पाइपलाइनें बिछी हुई हैं। अभी-अभी उत्तर प्रदेश के इलाके में कुछ विषय मेरे सामने भी आये थे। हम अमूमन किसानों के साथ बातचीत करके— यह सरकार कोई धक्का-मुक्की तो करने वाली नहीं है, बल्कि यह किसानों से बातचीत करके, किसानों से रजामंदी लेकर और स्थानीय सरकारों के सहयोग से यह पाइपलाइन डालेगी। पाइपलाइन देशहित में होती है, उसमें हम लोग कोई चीज़ जबरन लादने वाले नहीं हैं।

Programmes for tribal women

*183. SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA: Will the Minister of TRIBAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details of programme being implemented by the Government for tribal women: and

(b) the programme-wise grants provided during last year?

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI JUAL ORAM): (a) and (b) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) Tribal Sub Plans (TSP) of Central and State/UT Governments provide for various developmental/welfare programmes of Scheduled Tribes. The State Plan component *i.e.* TSP constitutes for more than two thirds of the total outlay of the TSP. The Ministry of Tribal Affairs supplements efforts of various line Ministries and Department of Central Government for development of Scheduled Tribes. The Ministry's various programme interventions are guided by literacy level of Scheduled Tribes, primarily that of Girls, since the year 2014-15. The Project Appraisal Committee headed by Secretary, Tribal Affairs with representatives of States and erstwhile Planning Commission amongst others provide emphasis on due share of women beneficiaries for skill, vocational training amongst other things.

Specific programmes of the Ministry include:

1. Setting Educational Complex amongst ST Girls in low literacy Districts
2. Adivasi Mahila Sashaktikaran Yojana (AMSY) through National Scheduled Tribe Finance and Development Corporation
3. 50 % women in Exchange of visits by Tribals